भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1055

(जिसका उत्तर सोमवार, 02 दिसंबर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

एमसीए वी3.0 पोर्टल के लाभार्थी

1055. श्री अरुण भारती:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डिजिटल कारपोरेट अनुपालन अवसंरचना की स्थापना के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा ई-शासन में वृद्धि करने के लिए शुरू किए गए एमसीए वी3.0 पोर्टल का ब्यौरा क्या है और एमसीए वी3.0 पोर्टल के लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार ने प्रतिस्पर्धा विरोधी परिपाटी में कृत्रिम आसूचना के प्रभाव को समझने के लिए कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं के संचालन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत उपयोग को कम करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): एमसीए21 पोर्टल 2006 में कारपोरेट फाइलिंग को डिजिटाइज़ करने, अनुपालन में सुधार करने और एमसीए सेवाओं तक सुरक्षित पहुंच प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। एमसीए21 का संस्करण-3 प्रवर्तन को और मजबूत करने, व्यवसाय में सुगमता को बढ़ावा देने और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। एमसीए21 वी3 के माध्यम से, वेब फाइलिंग, ई-एडजुडिकेशन, ई-कंसल्टेशन, ई-बुक, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आदि जैसी कार्यक्षमताओं को पेश किया गया है। लगभग 21.40 लाख कंपनियां और एलएलपी एमसीए21 पोर्टल की सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, निदेशकों, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनलों, कंपनी नोडल अधिकारियों सहित 60 लाख से अधिक व्यक्तिगत उपयोगकर्ता सीधे एमसीए21 सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं।

(ग) और (घ): भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और प्रतिस्पर्धा पर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी, गुरुग्राम (एमडीआईएस) द्वारा एक अध्ययन शुरू किया है।

******